



जल है तो कल है

सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

प्रेरणा

सुनो अधिक से अधिक, बोलो कम से कम।

www.jalandharbreeze.com

JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-5 • 21 JUNE TO 27 JUNE 2024 • VOLUME 47 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges & *Pay Money after the visa

•IELTS •STUDY ABROAD

Canada, Australia, USA, U.K, Singapore, EUROPE

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल को मिली जमानत

रेगुलर बेल मिलने पर आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल

नई दिल्ली. दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को शराब घोटाले से जुड़े माल लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि पर ये राहत मिली है। ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा था जिस कोर्ट ने खारिज कर दिया। राज जेज कोर्ट ने कहा कि एक लाख रुपये के मुचलके पर आज यानी शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले दिल्ली सीएम को मई में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी और इसके बाद चुनाव खत्म होते ही उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंजर करने का आदेश दिया गया था। अब उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है, इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी में भी खुशी की लहर है।



आम तौर पर मुंबई और गुजरात में आभूषण व्यवसाय में प्रचलित है। केजरीवाल ने जमानत मिलने के लिए बार-बार समन की अवहेलना करने को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा।

ईडी ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल ने नौ समन की अवहेलना करने के बावजूद हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि, केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। सीएम के वकील ने अदालत में कहा कि बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने दोषी होने की बात कबूल की है। वे यहां संत नहीं हैं, वे लोग खुद दामागि हैं बल्कि ऐसा भी लगता है कि उनमें जमानत और माफी दिए जाने का वादा किया गया था। सीएम के वकील ने कहा कि परिस्थितियों को इंटरनली ऐसे जोड़ा जाना चाहिए कि ईडी को सख्त सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है तो अनुमोदनकर्ताओं को ईडी के 100 करोड़ रुपये साउथ ग्रुप

से आए थे। ये सभी बयान हैं। कोई सबूत नहीं है। ईडी और सीबीआई के अनुसार साउथ ग्रुप राजनेताओं, व्यापारिक लोगों और अन्य लोगों का एक गिरोह है जिन्होंने शराब लाइसेंस के लिए पैरवी की। इसके लिए उन्होंने दिल्ली को सतारूढ़ पार्टी को रिश्वत दी। केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि कई सह-अभियुक्तों के बयानों में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि अगर कमी को पूरा करने के लिए एक और बयान दर्ज किया जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।

जांच हमेशा अंतहीन होती है। वे जब चाहें किसी को भी फंसा देते हैं। यह उत्पीड़न का सबसे बड़ा साधन है। बुधवार को अपनी दलीलें आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से संतुष्ट होने के बाद मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी थी कि उनके द्वारा न्याय से बचने या जांच या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। सीएम के वकील ने कहा कि केजरीवाल के इस तर्क को खारिज करते हुए कि ईडी को उनके खिलाफ एकमात्र सबूत सिर्फ बयान मिले थे। केजरीवाल ने कहा कि जब सबूत सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है तो अनुमोदनकर्ताओं को सबूत बनाया जाता है।

भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला : पीएम मोदी

श्रीनगर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में 'एम्पावरिंग यूथ, ट्रांसफॉर्मिंग जेएंडके' कार्यक्रम में शामिल हुए। वह 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्रीनगर में पीएम मोदी ने नए रंगरूटों को सरकारी सेवा नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान मोदी ने कहा कि लोगों की आकांक्षाएं सर्वाकालिक उच्च स्तर पर हैं और यह किसी देश के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। जब आकांक्षाएं ऊंची होती हैं तो लोगों की अपेक्षाएं भी ऊंची होती हैं। ऐसे मापदंडों पर हमारा मूल्यांकन करने के बाद जनता ने हमें तीसरी बार चुना। एक आकांक्षी समाज दूसरा काम नहीं देता। इसका एकमात्र पैरामीटर प्रदर्शन है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम जम्मू-कश्मीर



में जो बदलाव देख रहे हैं, वह पिछले 10 साल के हमारे काम का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जनता को सिर्फ हम पर विश्वास और इस विश्वास व उनकी आकांक्षा को हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है। जनता को हमारी नीयत और नीतियों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर चलते हुए हमारी सरकार प्रदर्शन करके दिखाती

है, रिजल्ट लाकर दिखाती है। इसी प्रदर्शन के आधार पर 60 साल के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश में जनादेश मिला है। लोकसभा चुनाव में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है। मोदी ने कहा कि करीब 20 साल पहले देश ने अस्थिर सरकारों का एक लंबा दौर देखा था। 10 साल में पांच बार चुनाव हुए। देश चुनाव कराने में व्यस्त था और अनिश्चितता तथा अस्थिरता के कारण जब इसे शुरू होना था तब इसे रोक दिया गया। भारत अब इसे पीछे छोड़कर स्थिर सरकार के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। इसने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है और जम्मू-कश्मीर के लोगों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में

प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और इस लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू-कश्मीर की आवाज की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो ईमानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था। उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। आपने इस चुनाव में जम्हूरियत को जितया है। आपने पिछले 35-40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल-370 की दीवार अब गिर चुकी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इस क्षेत्र की हमारी बेटियां और कमजोर वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया।



जालंधर वेस्ट के लोगो की सुविधाएं प्राथमिकता : शीतल अंगुराल

बदहाल सीवरेज, गंदे पानी की सफाई एवं खराब कानून व्यवस्था को आधार बना जालंधर वेस्ट जीतेंगे : सुशील शर्मा

• जालंधर ब्रीज, जालंधर

भारतीय जनता पार्टी जालंधर वेस्ट हल्के से उम्मीदवार शीतल अंगुराल के नामांकन भरने से पहले रोड शो निकाला। इस अवसर पर शीतल अंगुराल ने नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जालंधर वेस्ट के लोगो की सुविधाएं प्राथमिकता है अगर मैं स्वार्थी होता तो सरकार से इन्तौफा ना देता और सरकारी सुविधाओं का आनंद लेता। उन्होंने वेस्ट हल्के की जनता को विश्वास दिलाया कि वह सदैव जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं से पूरी तरह प्रभावित और आश्वस्त हैं और इस बार जालंधर वेस्ट से भाजपा का कमल खिलेगा।

लडेंगे और जीतेंगे। रिंकु ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के देश का विकास कर रही है और केंद्र की लाभकारी योजनाओं को लागू किया है। जालंधर वेस्ट के मतदाता भाजपा को जिताने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वो भाजपा प्रत्याशी शीतल अंगुराल को एक बड़ी लीड के साथ विजयी बनाएंगे तथा भाजपा वेस्ट हल्के के चौमुखी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, पूर्व सांसद सुशील रिंकु, नरिंद्र सिंह रैना, पूर्व एमएलए दिनेश बब्बू, विधायक मुकेरिया जंगी लाल महाजन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोरंजन कालिया, प्रदेश महामंत्री राकेश राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष केडी भंडारी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा, जिला महामंत्री अशोक सरीन हिक्की, राजेश कपूर और अमरजीत सिंह गोल्डी, राजन अंगुराल, जिला सचिव अमित भाटिया, जिला मीडिया इंचार्ज तरुण कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी, जिले के सभी मोर्चे और सैल, सभी मंडल अध्यक्ष और वेस्ट हल्के के हर वृथ से कार्यकर्ता उपस्थित थे।

यूजीसी नेट परीक्षा रद्द, फिर से होगा एग्जाम

केंद्र सरकार ने गहन जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने का लिया फैसला

नई दिल्ली. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शिता और शुचितता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही गहन जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिले इन्फुट से पता चला है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। पेपर लीक होने की संभावना भी जताई गई है। जिक्रयोग्य है कि नेट 2024 आयोजित करने वाली एनटीए ने ही यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को भी 18 जून 2024 को देश के कई शहरों में आयोजित कराया था।

यूजीसी नेट 18 जून को देशभर के 317 शहरों में 1200 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराया गया था जिसमें 11 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। यूजीसी-नेट परीक्षा के जरिये विश्वविद्यालय व कालेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की पात्रता निर्धारित होती है। इसके आधार पर ही उनकी सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है। इस बार इस परीक्षा के जरिये यूजीसी ने पीएचडी में दाखिला देने का फैसला लिया था। एनटीए की परीक्षाओं में एक के बाद गड़बड़ी के पीछे वहां चल रही ठेके की व्यवस्था को बड़ी वजह माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, एनटीए के पास इन परीक्षाओं को कराने का अपना खुद का कोई अमला या विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि यह परीक्षाएं आउटसोर्सिंग के जरिये कराती है। कई ऐसे एजेंसियां भी शामिल हैं, जिनके पास परीक्षा का न तो कोई अनुभव है और न कोई संसाधन है।

गैर-कानूनी हथियारों और नार्को-आतंकवाद हवाला रैकेट का पर्दाफाश, मुख्य साजिशकर्ता समेत 8 मुलजिम गिरफ्तार

गिरफ्तार साजिशकर्ता रणजीत काका पाकिस्तानी तस्करों के साथ सीधे संपर्क में था: सी. पी. अमृतसर रणजीत सिंह दिल्ली

• जालंधर ब्रीज, चंडीढ़/अमृतसर

अमृतसर कमिश्नर पुलिस ने 10 दिनों तक चल ऑपरेशन के दौरान सीमा पर से चलाए जा रहे गैर-कानूनी हथियारों और नार्को टेररिज्म हवाला रैकेट का पर्दाफाश करते हुए मुख्य साजिशकर्ता जिसकी पहचान रणजीत सिंह उर्फ काका के तौर पर हुई है, समेत आठ मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी गुरुवार को यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। डीजीपी ने बताया की मुख्य साजिशकर्ता के अलावा गिरफ्तार किये गए अन्य व्यक्तियों की पहचान रजिन्दर उर्फ राजा, अभिषेक उर्फ अंभ, विशाल उर्फ शालू, लवप्रीत उर्फ कालू, गुरभज उर्फ भिजा, गुरजट और जसपाल सभी निवासी घरिंडा अमृतसर, के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया की पुलिस टीमों ने उक्त मुलजिमों के पास से 4.10 किलो हेरोइन, दो पिस्तौल जिनमें पाकिस्तान का बना जिगाणा



पिस्तौल और .32 बोर का पिस्तौल शामिल है समेत 45 जिंदा कारतूस और 2.07 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद हुई है। इसके अलावा दोषियों के पास से सात वाहन: - हुंडई वरना, महेंद्रा थार, हुंडई आई-20, मारुति स्विफ्ट डिझायर, मारुति जैन, ऐक्टिवा स्कूटर और स्पेंडोर मोटरसाईकल भी बरामद किये गए हैं। डीजीपी ने कहा की सरहद पर संबंधों और हवाला गतिविधियों में शामिल अन्य गिरोहों को पकड़ने के लिए मुहिम अभी भी जारी है। यह कार्यवाही अमृतसर कमिश्नर पुलिस की तरफ से बारीकी के साथ आली-पिछली कड़ियों की जांच के बाद एक स्थानीय नशा

नीट मामले की जांच के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी

नई दिल्ली. मंडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के दौरान अनियमितताओं के आरोपों के बीच केंद्र ने गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान ने एक ब्रीफिंग में कहा कि हम शून्य-शुट परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और एनटीए कामकाज में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम पारदर्शिता से



कोई समझौता नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा के संदर्भ में हम बिहार सरकार के संपर्क में हैं। हमें पटना से कुछ सूचनाएं मिल रही हैं। पुलिस जांच कर रही है और उनके द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। विश्वसनीय जानकारी के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने जा रही

है। उस उच्च स्तरीय समिति से एनटीए, इसकी संरचना, कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को और बेहतर बनाने के लिए सिफारिशों की अपेक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर एनटीए के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधान ने कहा कि एक अलग घटना (बिहार पेपर लीक) का असर उन लाखों छात्रों पर नहीं पड़ना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। उन्होंने कहा कि हमें जिम्मेदारी लेते हुए व्यवस्था को सुधारना होगा।

246 बड़े नशा तस्करों के सुरक्षित टिकानों पर छापेमारी

नशे को जड़ से खत्म करने के लिए चलाए जा रहे विशेष मुहिम के आज पाँचवे दिन, पंजाब पुलिस ने बड़े नशा तस्करों या बड़ी मछलियों, जो इस समय जमानत पर बाहर है, पर शिकंजा कसते राज्य भर में स्थित उनके सुरक्षित टिकानों पर छापेमारी की। यह आपरेशन डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही समय चलाया गया। स्पेशल डीजीपी ला एंड आर्डर अर्पित शुक्ला, जो इस राज्य स्तरीय कार्यवाही की निजी तौर पर निगरानी कर रहे थे, ने बताया कि राज्य में 257 एनडीपीएस मामलों में 356 बड़े नशा तस्कर 2 किलो या इससे अधिक नशीले पदार्थों सहित पकड़े गए हैं, जिनमें से 246 दोषी जमानत पर बाहर है और पिछले पाँच सालों से सक्रिय है। उन्होंने कहा कि नशे के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए चलाए जा रहे इस आपरेशन को सफल बनाने के लिए सभी 246 बड़े नशा तस्करों की सूची सभी सीपीओ/एसएसपीज के साथ सांझी की गई थी और उनको इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टरों के नेतृत्व में मजबूत पुलिस पार्टियों तैनात करके तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। स्पेशल डीजीपी ने कहा कि 1200 पुलिस मुलाजिमों की भागीदारी वाली 113 से अधिक पुलिस पार्टियों ने 246 बड़े तस्करों के टिकानों पर छापेमारी की और उनमें से 188 की चैकिंग की।

तस्कर रजिन्दर उर्फ राजा (22) निवासी गांव घरिंडा, अमृतसर की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। जिक्रयोग्य है की उक्त नशा तस्कर को 500 ग्राम हेरोइन, 40,000 रुपए ड्रग मनी, वरना कार और एक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था। मुलाजिम रजिन्दर राजा अमृतसर देहाती पुलिस द्वारा कल के मामले में वांछित था। पुलिस कमिश्नर अमृतसर रणजीत सिंह दिल्ली ने बताया की इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह के नेतृत्व वाली सी.आई.ए। की टीम और पुलिस थाना इस्लामाबाद की टीम ने एडीसीपी जॉन-1 डॉ. दर्पण आहलुवालिया और ए. डी. सी. पी. डिटेक्टिव नवजोत सिंह संधु की निगरानी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

जून के आखिरी में इन जगहों पर जाने का बनाएं प्लान, मजे में बीतेंगे दिन

TRAVELLING

जून महीने के आखिरी दिनों में अगर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन जगहों पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं।

• जालंधर ब्रीज. फीचर

अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं तो तो जून के महीने में आखिरी दिनों में कुछ जगह पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दरअसल जून के आखिरी दिनों में बारिश होना शुरू हो जाती है। ऐसे में भारत की कुछ जगहों की सुंदरता काफी हद तक बढ़ जाती है। इस दौरान आप भी कुछ बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर करने का प्लान बना सकते हैं। अगर आप इन जगहों को एक बार देख लेंगे तो दोबारा आने का प्लान हर बार बनाएंगे। जून महीने के आखिरी दिनों में घूमने के लिए बेस्ट प्लेस- कर्नाटक का चिकमगलूर दक्षिण भारत में जून में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहां का हेल्थी और हनुमान गुंडी झरना सबसे फेमस है। अगर आपको वाटरफॉल पसंद है तो यहां पर आपको जरूर खुशी मिलेगी। भद्रा बांध, हनुमान गुंडी झरना, मधु गुंडी झरना, हिरिकोलाले झील, कॉफी संग्रहालय और वीरा नारायण मंदिर यहां घूमने के लिए बेस्ट हैं।

कसौली - कसौली एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हर उम्र के लोग आना पसंद करते हैं। यह उन पर्यटकों का स्वगत करता है जो ऐतिहासिक जगहों पर जाना पसंद करते हैं। गोरखा किला, कृष्ण भवन मंदिर, क्राइस्ट चर्च और मानकी पॉइंट कसौली घूमने के लिए बेस्ट हैं।

पालमपुर - इस जगह को 'उत्तर पश्चिमी भारत की चाय राजधानी' के तौर पर भी जाना जाता है। ये जगह पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां पर नेवगल खाद, सौरभ बन विहार और चाय बागान को देख सकते हैं। शांति पूर्ण छुट्टियां बिताने के लिए ये जगह बेस्ट है।

वायनाड - वायनाड केरल का एक शहर है जो हरियाली से घिरा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। यहां मीनमुट्टी झरना, चेम्बरा पीक, थिरुनेली मंदिर और कंधनपारा झरना जरूर एक्सप्लोर करें।

मलाणा - हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव मलाणा अपनी अनूठी संस्कृति के कारण पर्यटकों के बीच फेमस है। हिमालय से घिरा, यह शांत पहाड़ी शहर जून में भारत के सबसे अच्छी जगहों की लिस्ट में शामिल है। मलाणा में घूमने की के लिए खीरगंगा, मणिकरण और तोशा है।



SKIN CARE

लौट आया फिर से लटकती झालरों का फैशन, जानें कैसे करें फ्रिज वाले कपड़ों को स्टाइल

फैशन के गलियारों में हर नया लुक पिछले किसी लुक से प्रेरणा लिए होता है। ऐसा ही एक ट्रेंड है फ्रिज फैशन। यह नब्बे के दशक के बाद एक बार फिर वापस आ चुका है। फ्रिज यानी झालर। कैसे इसे तरह-तरह से बनाएं अपने लुक का हिस्सा, बता रही हैं रिश्मा आनंद



• जालंधर ब्रीज . फीचर

मैं हूँ ना फिल्म का गाना चले जैसे हवाए... में अमृता राव का लुक लोगों को बहुत भाया था। और उसके बाद उस तरह के टॉप की बहारा आ गई थी। हालांकि यह फैशन तब भी नया नहीं था। इसके इतिहास की बात की जाए तो यह 1920 में भी काफी ज्यादा चलन में रहा। लेकिन दशकों बाद एक बार फिर यह फैशन जगत में वापसी कर चुका है। हाल ही में कई बॉलिवुड एक्ट्रेस और मॉडल्स ने फ्रिज को अपनाया है। इनमें आलिया भट्ट से लेकर शहनाज गिल और प्रियंका चोपड़ा जोनस जैसे जान-माने नाम शामिल हैं। लेकिन यह फैशन सिर्फ इस हाई एंड मार्केट तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसे आप भी आसानी से अपने नए लुक के लिए अपना सकती हैं। कैसे? आइए जानें:

हाइलाइट करने वाली जगह पहनें फ्रिज

जब किसी विशेष तरह के फैशन या आउटफिट में किसी एक खास फैशन लुक को शामिल करना होता है, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वह केवल शरीर के उस हिस्से में ही आए जिसे हम हाइलाइट करना चाहते हैं। इस बावत फैशन डिजाइनर श्रुति संचेती कहती हैं कि जरूरी नहीं है कि हर तरह का लुक हर किसी पर फवे।

लेकिन आउटफिट के केवल एक हिस्से में किसी फैशन ट्रेंड को शामिल करते समय हमें अपने बॉडी टाइप का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि किसी भी नई चीज या नए पैटर्न पर निगाह अपने आप ही चली जाती है। अब ऐसे में आपको केवल अपने उसी हिस्से पर फ्रिज पहनना चाहिए, जिसे आप छिपाना ना चाहें। जैसे, अगर आपकी बाहें खूबसूरत हैं तो आप आरस्तीनों पर फ्रिज लगा सकती हैं, लेकिन अगर पेट में चर्बी है तो पेट के हिस्से में फ्रिज वाले कपड़े पहनने से बचें।

लुक को करें संतुलित

फैशनबल कपड़ों के साथ फैशन सेंस होना भी जरूरी है। आपके कपड़ों में फ्रिज सब्जी में नमक की तरह काम करना चाहिए। यानी लुक का संतुलित होना भी जरूरी है। जोस टॉप में से किसी एक में ही फ्रिज रखिए। अगर बैग फ्रिज वाला है तो कपड़ों में लेयरिंग या फ्रिज से बचें। इसी तरह अगर फ्रिज वाली वन पीस ड्रेस है, तो ध्यान रखें कि उसमें जरूरत से ज्यादा फ्रिज न हो।

लेयरिंग के साथ फ्रिज

इन दोनों फ्रिज को खाली लटकाने की जगह उन्हें लेयरिंग में पहनने का फैशन भी चल रहा है। इसमें कपड़े की अंदर की लेयर के ऊपर फ्रिज होती है, जो केवल एक तरफ या दोनों तरफ से ही सिली हुई होती है। ऐसी फ्रिज न्यूयॉर्क फैशन वीक 2024 में खूब नजर आई। इसके साथ ही स्कर्ट में लेयरिंग के साथ फ्रिज और बाह के बाहरी हिस्से में फ्रिज भी देखने को मिली। इस तरह के फ्रिज का चलन एक्ससेसरीज में भी है।

क्रोशिया की फ्रिज

यू तो ग्लैम फ्रिज चमकदार नजर आ रही हैं, लेकिन मौसम का ख्याल रखते हुए क्रोशिया की फ्रिज वाले टॉप भी देखे जा सकते हैं। इनमें क्रोशिया के टॉप की किनारी पर फ्रिज होती है, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्रोशिया में इस तरह के फ्रिज वाले टॉप ही नहीं बल्कि स्कर्ट, श्रग और वन पीस ड्रेस भी देखी जा सकती हैं।

सोच-समझकर चुनें फ्रिज

इन दिनों बहुत पतली फ्रिज का चलन है। इससे बहुत आकर्षक लुक मिलता है। पर, अगर आप चौड़ी फ्रिज पहनना चाहती हैं तो आपको अपने बॉडी टाइप को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की फ्रिज से शरीर और चौड़ा लगता है। ऐसा करने से बचें। वहीं, अगर बॉटम में फ्रिज रख रही हैं तो उसकी लंबाई शॉर्ट से मीडियम तक ही होनी चाहिए।

घर में नहीं है फ्रिज तब भी बना सकते हैं ढेर सारी आइसक्रीम, यहां जानें तरीका

गर्मियों में तो जितनी भी आइसक्रीम खाने को मिल जाए उतनी ही कम है। बाजार वाली सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती और ना ही खाकर मन भरता। बस इसलिए कुछ लोग घर पर आइसक्रीम बनाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर घर पर फ्रिज ही ना हो तो क्या करें। आज हम आपको बिना फ्रिज के ही आइसक्रीम जमाना सीखने वाले हैं।



• जालंधर ब्रीज. रसिपी

चिलचिलाती गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाना भला किसे नहीं पसंद। वैसे भी आजकल तो इंटरनेट पर आइसक्रीम बनाने की तमाम रसिपीज पड़ी हुई हैं। जैसी मर्जी वैसे प्लेवर की आइसक्रीम का मजा घर पर बैठकर ही उठाया जा सकता है। फिर क्यों बाजार वाली केमिकल से भरी आइसक्रीम को खाना, लेकिन उसके लिए जरूरत है फ्रिज की। बिना इसके तो आइसक्रीम बनाने की रसिपी बता रहे हैं। अब आम की सोच भी नहीं सकते, हैं ना। लेकिन आज हम आपके लिए ऐसा तरीका खोजकर लाए हैं जहां आपको फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप घर पर ही ढेर सारी आइसक्रीम का आनंद उठा पाएंगे।

बिना फ्रिज के बना रहे हैं आम की आइसक्रीम, तो चाहिए होंगी ये चीजें : बिना फ्रिज के आइसक्रीम बनाना बेहद ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने ही घर

पर एक फ्रिज तैयार करेंगे। डरिए मत इसमें कोई झंझट या तामझाम नहीं है। इसके लिए बस आपको दो जिप लॉक बैग (वही प्लास्टिक के बैग जो आगे से बंद हो जाते हैं) , थोड़े से बर्फ के टुकड़े, आधा कप सेंधा नमक चाहिए होगा। बस आपका फ्रिज तैयार है।

वैसे तो आप इस तरीके से अपने मन पसन्द की कोई भी आइसक्रीम बना सकते हैं लेकिन यहां हम आपको आम की आइसक्रीम की रसिपी बता रहे हैं। अब आम की आइसक्रीम बना रहे हैं तो जाहिर है आम की जरूरत होगी। इसके साथ ही थोड़ी चीनी या मिश्री, मलाई और दूध की भी जरूरत होगी।

ये है बिना फ्रिज आइसक्रीम जमाने का आसान तरीका : बिना फ्रिज के आइसक्रीम जमाने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आइसक्रीम बना रहे हैं उसकी तैयारी कर लेनी है। यहां हम आम की आइसक्रीम बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके

मिश्रण को तैयार करेंगे। आम का गूदा निकाल लें। अब एक मिक्सर में उसे डालें। अब उसमें स्वाद अनुसार चीनी, आधा कप दूध और थोड़ी सी मलाई या क्रीम डाल दें। सब कुछ मिलकर एक घोल तैयार हो जाएगा। अब बारी है इसे बिना फ्रिज के जमाने की। इसके लिए आपको एक प्लास्टिक बैग में बर्फ के टुकड़ों को भर लेना है। बर्फ के टुकड़े आप आसानी से किसी दुकान से खरीद सकते हैं। अब उसमें आधा कप सेंधा नमक डाल लीजिए। अपने आइसक्रीम के मिक्सचर को भी एक दूसरे प्लास्टिक बैग में पलट लीजिए। इस मिक्सर वाले बैग को बर्फ वाले बैग में बर्फ के बीचों बीच रख दीजिए। पूरे मिक्सचर वाले बैग को ऊपर से भी बर्फ से ढक दीजिए। अब आप इसे तौलिया से ढक दें और पांच मिनट के लिए हाथों से हिलाते रहें। बस पांच मिनट में ही आप देखेंगे कि आपकी आइसक्रीम पूरी तरह तैयार है।

बच्चों की सेहत के लिए हार्मफुल है पैकेटबंद सेरेलक, घर पर करे तैयार

बाजार में मिल रहे पैकेटबंद सेरेलक अगर बच्चे की सेहत के लिए हार्मफुल हैं तो आप घर में बेबी फूड पाउडर बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस इस आसान से तरीके से घर में ही बनाकर रख लें सेरेलक।



Parenting

जालंधर ब्रीज (फीचर)

बाजार में मिलने वाले बच्चों के लिए फूड खासतौर पर सेरेलक को भी अब हार्मफुल बताया जा रहा है। इन सेरेलक में चीनी की ज्यादा मात्रा छोटे बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में आप अपने बच्चे के लिए घर में ही हेल्दी और टेस्टी सेरेलक तैयार कर सकती हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। बस जान लें इसे बनाने का तरीका।

कितने बड़े बच्चे को सेरेलक खिलाया जाए छह महीने का हो जाने के बाद बच्चों को अनाज खिलाया जाता है। ऐसे में दाल चावल को मिलाकर सेरेलक तैयार किया जाता है। ये छह महीने से ऊपर के बच्चों को खिलाया जाता है। जो बच्चों के डाइजेशन के हिसाब से होता है और आसानी से पच जाता है। इस तरह से अनाज खिलाने से बच्चे आसानी से खाते हैं और उनका वजन भी बढ़ता है।

सेरेलक बनाने की सामग्री

- एक कप चावल
- दो चम्मच मूंग की दाल
- दो चम्मच मसूर की दाल
- दो चम्मच काला चना
- दो चम्मच गूँह की दलिया
- पांच से छह बादाम
- सेरेलक बनाने का तरीका
- किसी बड़े बर्तन में सारे अनाज को अच्छी तरह से बोनकर चक कर लें कि कहीं कंकड़ या गंदगी ना हो।
- अब सारे अनाज को अच्छी तरह से पानी से धो लें।
- फिर किसी साफ तौलिये पर फैलाकर इन्हें सुखाएं। जल्दी सुखाने के लिए चाहे तो थोड़ी देर धूप में डाल दें।
- अब कड़ाही में चावलों को डालें और ड्राई रोस्ट कर लें। साथ ही गूँह की दलिया को भी रोस्ट करें।
- सारी दालों को भी ड्राई रोस्ट कर लें।
- ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पाउडर बना लें।
- इसे छलनी से छान लें। जिससे मोटे कण निकल जाएं।
- बस तैयार है सेरेलक, इसे जब चाहे तो दूध में डालकर धीमी आंच में पकाएं और बच्चे को खिलाएं।

डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल में बताई विधि, तरीकों व दावों को केवल सुझाव के रूप में लें। इस तरह के किसी भी उपचार/दवा/डाइट और सुझाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह लें।

बार-बार होता है बर्फ खाने का मन? यूं ना करें इग्नोर, हो सकती है बड़ी वजह

HEALTH

गर्मियों के मौसम में ठंडी-ठंडी चीजें खाना सभी को पसंद होता है। लेकिन कुछ लोग बार-बार फ्रिज में जाकर बर्फ का टुकड़ा चबाते रहते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि बार-बार बर्फ खाने की क्रेविंग होने के पीछे बड़े कारण भी हो सकते हैं। आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे।

• जालंधर ब्रीज. हेल्थ केयर

गर्मियों के मौसम में कुछ भी ठंडा-ठंडा मिल जाए तो राहत मिल जाती है। बर्फाला पानी, ठंडी आइसक्रीम, शरबत या कोल्ड ड्रिंक जो भी हो थोड़ी देर के लिए हमें इस चुभती गर्मी से छुटकारा तो दिला ही देता है। ऐसे में कुछ लोग फ्रिज से सादी बर्फ निकालकर चबाते हैं। हालांकि इसमें तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप एक दो बार ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका बार-बार कच्ची बर्फ चबाने का मन करता है तो इसके पीछे कई बीमारियों के संकेत छुपे हो सकते हैं। आज हम आपको इसी के पीछे का कारण बताने वाले हैं।

क्यों होता है बार-बार बर्फ खाने का मन

बार-बार बर्फ खाने की क्रेविंग उठने की समस्या को 'पाइका डिस्ऑर्डर' का नाम भी दिया गया है। यह आमतौर पर बच्चे और गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है लेकिन यह किसी को भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स की मानें तो जिन लोगों के अंदर आयरन की कमी होती है उन्हें बार-बार बर्फ खाने की क्रेविंग होती है। इसके साथ ही मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन या स्ट्रेस की स्थिति से गुजर रहा है तब भी उसे यह इटिंग डिस्ऑर्डर हो सकता



है। कुछ लोगों में डिहाइड्रेशन भी इसका एक प्रमुख कारण है साथ ही प्रेगनेंसी, पीरियड्स और स्तनपान के समय भी ऐसी इच्छा हो सकती है।

क्या है इसके नुकसान

अगर अपनी क्रेविंग के चलते आप बार-बार बर्फ खा रहे हैं

तो इसके कुछ साइडइफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही कि आप अपनी बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम हो लेकिन आप उसपर ध्यान ही नहीं दे रहे हों इसलिए इसके पीछे का कारण जानना बेहद जरूरी है। इसे यूं ही इग्नोर न करें। अगर समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह लेने में भी कोई डील ना बरतें।

बर्फ खाने से आपके दांतों को भी इसकी मार झेलनी पड़ सकती है। बर्फ हमारे दांतों की बाहरी परत के लिए नुकसानदायक होता है जिससे काफी सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही कई बार पेट में इन्फेक्शन और कब्ज की शिकायत भी हो सकती है।

नोट : इस खबर में बताए गए सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। इसलिए किसी भी उपचार/दवा/डाइट को अमल करने से पहले डॉक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया

पृष्ठभूमि: नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में 40 कक्षाओं वाले दो शैक्षणिक खंड हैं। इनमें 1900 छात्र बैठ सकते हैं। इसमें 300-300 सीटों की क्षमता वाले दो सभागार, लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास और अन्य कई सुविधाएँ हैं, जिनमें एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक एम्फ़ीथिएटर, एक संचाय क्लब और एक खेल परिसर शामिल हैं। यह परिसर एक 'नेट जीरो' हरित परिसर है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र, घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकाय और कई अन्य पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं से लैस है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास से गहरा नाता है। लगभग 1600 साल पहले स्थापित मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। नालंदा के खंडहरों को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था।

• जालंधर ब्रीज . बिहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिक्षा सम्मेलन (ईएसए) के देशों के बीच सहयोग प्रणाली के रूप में की गई है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेने के 10 दिन के अंतराल में नालंदा आने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह भारत का विकास-यात्रा की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं है, यह एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा मूल है और मंत्र भी है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, भले ही पुस्तकें आग में जल जाएं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नवीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के स्वर्ण युग का शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा के प्राचीन अवशेषों के निकट इसका पुनरुद्धार विश्व को भारत की क्षमताओं से परिचित कराएगा। इससे विश्व को यह जानकारी मिलेगी कि प्रबल मानवीय मूल्यों वाले राष्ट्र, इतिहास का कायाकल्प करके एक बेहतर विश्व का निर्माण करने में सक्षम हैं।

मोदी ने कहा कि नालंदा में विश्व, एशिया और कई देशों की विरासत समाहित है और इसका पुनरुद्धार सिर्फ भारतीय पहलुओं के पुनरुद्धार तक सीमित नहीं है। आज के उद्घाटन में इन देशों की उपस्थिति से यह स्पष्ट है कि उन्होंने नालंदा परियोजना में मित्र देशों के योगदान

को स्वीकार किया। उन्होंने नालंदा में परिलक्षित होने वाली गौरव को लौटाने के लिए बिहार के लोगों के दृढ़ संकल्प को भी प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री ने नालंदा को भारत की संस्कृति और परंपराओं का जीवंत केंद्र बताते हुए कहा कि नालंदा का अर्थ ज्ञान और शिक्षा का निरंतर प्रवाह है और यही शिक्षा के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सोच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, "शिक्षा सीमाओं से परे है। यह मूल्यों और विचारों को आकार प्रदान करते हुए हुए उन्हें विकसित करती है।" उन्होंने कहा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को उनकी अलग-अलग पहचान और राष्ट्रियता के बावजूद प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने आधुनिक रूप में नवीनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में उन्हीं प्राचीन परंपराओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि 20 से अधिक देशों के छात्र पहले से ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आवर्ण उदाहरण है।

प्रधानमंत्री ने शिक्षा को मानव-कल्याण के साधन के रूप में स्वीकार करने की भारतीय परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में कहा कि योग दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि योग की इतनी सारी विधाएँ विकसित करने के बावजूद, भारत में किसी ने भी योग पर एकाधिकार नहीं जताया। इसी तरह, भारत ने आयुर्वेद को संपूर्ण विश्व के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री ने निरंतरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया और कहा कि भारत में, हमने प्रगति और पर्यावरण को एक साथ आगे बढ़ाया है। इसने भारत को स्वस्थ जीवन शैली (मिशन लाइफ) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन



जैसी पहल करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर अग्रणी नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो वेस्ट मॉडल के साथ निरंतरता की भावना को आगे बढ़ाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के विकास से अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जुड़ो गहरी होती है और यह वैश्विक और विकसित देशों के अनुभव से साबित होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य कर रहा है तथा अपनी शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन है कि भारत, विश्व के सम्मुख शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है कि भारत की पहचान फिर से दुनिया के सर्वप्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में हो। प्रधानमंत्री ने अटल टिकरिंग लैब्स जैसी पहलों का उल्लेख किया, जिनसे एक करोड़ से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। चंद्रयान और गगनयान अभियान से छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हुई है और स्टार्टअप इंडिया अभियान के माध्यम से भारत में 1.30 लाख स्टार्टअप शुरू हुए हैं। दस साल पहले स्टार्टअप की संख्या मात्र कुछ ही थी।

रिपोर्ट संख्या में पेटेंट और शोध पत्र दाखिल किए गए और शोधार्थियों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शोध कोष बनाया गया।

प्रधानमंत्री ने विश्व में सर्वाधिक उन्नत शोधोन्मुख उच्च शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ व्यापक और पूर्ण कौशल प्रणाली बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने वैश्विक रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालयों के बेहतर प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। पिछले 10 वर्षों में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में हाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने व्यूएस रैंकिंग में भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की संख्या 9 से बढ़कर 46 और टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में 13 से बढ़कर 100 होने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रत्येक सप्ताह देश में एक विश्वविद्यालय, हर दिन एक नया आईटीआई और दो नए कॉलेज तथा हर तीसरे दिन एक अटल टिकरिंग लैब खोली गई है। उन्होंने कहा कि भारत में आज 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं और भारतीय प्रबंधन संस्थानों की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। एम्स की संख्या लगभग तीन गुना बढ़कर 22 और

मैडिकल कॉलेजों की संख्या भी लगभग दोगुनी हो गई है। शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति का उल्लेख किया और कहा कि इसने भारत के युवाओं के सपनों को एक नया आयाम दिया है। मोदी ने भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग एवं डीकिन और बोलोगोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के नए परिसरों के देश में खुलने का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन सभी प्रयासों से भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान मिल रहे हैं। इससे हमारे मध्यम वर्ग के पैसे भी बच रहे हैं।

हाल ही में प्रमुख भारतीय संस्थानों के वैश्विक परिसरों के उद्घाटन का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने नालंदा के लिए भी यही आशा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है और भारत के युवाओं पर है। उन्होंने कहा कि भारत, भगवान बुद्ध की भूमि है और संपूर्ण विश्व लोकतंत्र की जननी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। उन्होंने कहा कि जब भारत कहता है 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य', तो विश्व उसके साथ खड़ा हो जाता है। जब भारत कहता है 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड', तो इसे दुनिया के भविष्य का मार्ग माना जाता है। जब भारत कहता है 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य', तो विश्व उसके विचारों का सम्मान करता है और उसे स्वीकार करता है। नालंदा की धरती सार्वभौमिक भाईचारे की इस भावना को एक नया आयाम दे सकती है। इसलिए, नालंदा के छात्रों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है।

नालंदा के छात्रों और विद्वानों को भारत का भविष्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने अमृत काल के अगले 25 वर्षों के महत्व को रेखांकित किया और उनसे नालंदा के 'मार्ग' और मूल्यों को अपने साथ लेकर चलने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे जिज्ञासु, साहसी और सबसे बढ़कर अपने लोगों के अनुरूप दयालु बनने को कहा तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नालंदा का ज्ञान, मानवता को दिशा प्रदान करेगा और भविष्य में यहां के युवा संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि नालंदा वैश्विक हित का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलेंकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री प्रविण मंगरिठ, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और स्मार्ट चोधरी, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. अरविंद पनागढ़िया और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अभय कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सरकारी दफ्तरों में यदि लोग परेशान हुए तो डिप्टी कमिश्नर जवाबदेह होंगे : मुख्यमंत्री



• जालंधर ब्रीज . चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री ने भगवंत सिंह मान ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि समूह डिप्टी कमिश्नर अपने-अपने जिलों के सरकारी दफ्तरों में आम लोगों को किसी भी तरह की असुविधा और परेशानी के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। यहाँ डिप्टी कमिश्नरों के साथ मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को साफ-सुथरा, जवाबदेह और प्रभावशाली प्रशासन मुहैया करवाना राज्य सरकार का फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ही सबसे कारगर भूमिका निभा सकते हैं जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों में नागरिक केंद्रित सेवाएँ निर्विघ्न तौर पर मुहैया करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों का यह फर्ज बनता है कि वे यह यकीनी बनाएँ कि उनके सम्बन्धित जिलों के लोगों को सरकारी दफ्तरों का दौरा करते समय किसी किसम की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस काम में ढील बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी और ऐसी किसी भी लापरवाही के लिए सम्बन्धित

डिप्टी कमिश्नर को जवाबदेह बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हर जिले में 'मुख्यमंत्री सहायता केंद्र' स्थापित करने का नवीन प्रयास लेकर आ रही है जिससे लोग इस सहायता केंद्र के द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। भगवंत सिंह मान ने बताया कि 'मुख्यमंत्री सहायता केंद्र' पर एक समर्पित अधिकारी उपस्थित रहेगा जो आम लोगों के रोज़मर्रा के प्रशासकीय कामकाज के साथ सम्बन्धित आवेदन-पत्र प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के प्रशासकीय कामों सम्बन्धी आवेदन-पत्र सम्बन्धित विभाग को भेजा जायेगा जिससे काम को तुरंत पूरा किया जा सके। इसी तरह राज्य सरकार से सम्बन्धित कामों को मुख्यमंत्री दफ्तर भेजा जायेगा जिनके हल के लिए इन आवेदन-पत्र को प्रशासकीय विभागों के पास भेजा जायेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 'चीफ़ मनिस्टर डैशबोर्ड' जिले भर में आम लोगों से उनकी अज़िबों और बकाया कामों के बारे फीडबैक लेने के साथ-साथ सामूची गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम लोगों के रोज़मर्रा के कामों को समयबद्ध और तुरंत पूरा करने को यकीनी बनाएगा।

कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूरे होने पर एनसीसी निदेशालय द्वारा सेमिनार का आयोजन

जालंधर ब्रीज (चंडीगढ़). एनसीसी निदेशालय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ (पीएचएचपीएंडसी) द्वारा मुख्यालय डीजी एनसीसी के तत्वावधान में आज डीएवी कॉलेज सेक्टर-10, चंडीगढ़ में एक प्रेक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूरे होने पर कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया, तथा इसने युवा एनसीसी कैडेटों को रक्षा बलों के वास्तविक नायकों के साथ बातचीत करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान किया। इस अवसर पर जनरल वीपी मलिक, पूर्व सेनाध्यक्ष (सेवानिवृत्त) और लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, उत्तरी कमान के पूर्व सेना कमांडर (सेवानिवृत्त) विशिष्ट अतिथि वक्ताओं में से थे।

अपने संबोधन में जनरल वीपी मलिक ने भविष्य के सैनिकों यानी एनसीसी कैडेटों को एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए इस मूल्यवान सेमिनार के आयोजन के लिए महानिदेशक एनसीसी और एडीजी एनसीसी (पीएचएचपीएंडसी) की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कैडेटों के लिए हमारे कारगिल नायकों की बहादुरी की कहानियों के बारे में जानने का वास्तविक माध्यम है। उन्होंने बताया कि यह सराहनीय है कि सरकार ने एनसीसी कैडेटों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है।

इस अवसर पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुबीरपाल सिंह ने मुख्य भाषण देते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के एनसीसी निदेशालय द्वारा आयोजित इस प्रेक सेमिनार में हम कारगिल में विजय के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अरली युद्ध नायकों और कारगिल ऑपरेशन में शामिल बहादुरों को अपने क्षेत्र के अनुभवों को साझा करके युवा कैडेटों को प्रेरित करने और उनसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है।

सीएम मान ने पुलिस अधिकारियों को दिया नशा तस्करों की गिरफ्तारी के एक हफ्ते में जायदाद ज़ब्त करने के आदेश

• जालंधर ब्रीज . चंडीगढ़

पंजाब में नशों के खतरे से निपटने की राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में इस श्राप के ख़ात्मे के लिए पंजाब सरकार ने बहु-पक्षीय रणनीति बनायी है।

यहाँ पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य की पुलिसिंग में कई सुधार लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदान की तैयारियों दौरान पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी मात्रा में नकदी और नशा पकड़ा है साथ ही नशों की स्पलाई के बारे में अहम जानकारियाँ जुटाई है। उन्होंने कहा कि यह ध्यान में आया है कि कई निचले स्तर के पुलिस मुलाजिमों की नशा तस्करों के साथ मिलीभूत है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अहम पहलकदमी करते राज्य सरकार ने दरजाबन्दी में सबसे निचले स्तर पर आते और लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात पुलिस मुलाजिमों की बड़े स्तर पर बदलियाँ की हैं।

मुख्य मंत्री ने कहा कि अलग-अलग डिवीज़नों में तैनात 10 हज़ार से अधिक पुलिस मुलाजिमों के तबादले



किए गए हैं और तैनातियों में रोटेशन की प्रक्रिया चल रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश में नशों की समगलिंग को रोकने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं क्योंकि उनको रिपोर्टें मिली है कि निचले स्तर पर कई पुलिस अफसरों की नशा तस्करों के साथ मिलीभूत है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की इन काली भंडों की शिनाख़्त की जायेगी और उनके विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जायेगी। मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर कोई नशों की समगलिंग में शामिल पाया गया तो पुलिस एक हफ्ते के अंदर-अंदर उसकी जायदाद ज़ब्त करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस नीति को मिशनरी भावना के साथ लागू करने के लिए कहा गया ताकि नशा तस्कारी पर नकेल कसी जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा

कि पंजाब पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए फोर्स में 10 हज़ार नए पद सृजित करने का फैसला किया गया है। मुख्य मंत्री ने कहा कि इससे आने वाले समय में एक तरफ अपराध को रोकने में मदद मिलेगी, दूसरे तरफ युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अमन और कानून की स्थिति बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस को अति-आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ लैस किया गया है और राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई सड़क सुरक्षा फोर्स सफलतापूर्वक काम कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस फोर्स ने अब तक सख़्त हादसों के बाद दो हज़ार से अधिक कीमती जानें बचाई है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को नशों विरुद्ध जंग को राज्य की भलाई के लिए एक आंदोलन में बदलने के लिए कहा गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब वह दिन चले गए, जब राज्य सरकार 'कमिशन' पर चलती थी। अब तो सरकार 'मिशन' की तरह चल रही है। इसी तरह राज्य में समगलिंग के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाले समारल्लों, गैंगस्टरों और आतंकवाहियों के साथ निपटने के लिए विस्तृत रणनीति बनाई गई है।

पीआईबी चंडीगढ़ के 'वार्तालाप' में नए कानूनी कोडों पर प्रकाश डाला गया

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम

• जालंधर ब्रीज . चंडीगढ़

चंडीगढ़ ने आज यूटी स्टेट गेस्टहाउस, चंडीगढ़ में एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंडीगढ़ और आस-पास के क्षेत्रों के पत्रकारों को तीन नए कानूनों से परिचित कराना था: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले हैं।

कंवरदीप कौर, आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) चंडीगढ़, इस सभा में मुख्य अतिथि और विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने इन नए कानूनों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "इन नए कानूनों के साथ, न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में प्रणाली अधिक कुशलता से आगे बढ़ेगी।" एसएसपी कंवरदीप कौर ने नए कानूनी ढांचे का अभिनव पहलुओं, विशेष रूप से न्याय वितरण प्रणाली को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विस्तार से बताया।

उन्होंने कहा, "नए कानूनों के तहत, टाइमस्टैम्पड साक्ष्य संग्रहीत किए जाएंगे और समय पर अदालतों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पूरे देश में सजा दरों में उल्लेखनीय सुधार होगा।" एसएसपी कंवरदीप कौर ने यह भी बताया कि चंडीगढ़ पुलिस के सभी जांच अधिकारियों को तीन नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि ये कानून कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू हों।"

"पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपक बजाज ने भी इस विषय पर बात की और इन कानूनों की दक्षता और आधुनिकीकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए हमारी कानूनी प्रणाली में व्यापक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उद्देश्य देरी को कम करना और समय पर न्याय सुनिश्चित करना है।" ये



एसएसपी कंवरदीप कौर ने चंडीगढ़ में पीआईबी मीडिया कार्यशाला में कानूनी सुधारों पर प्रकाश डाला।

कानून अतीत की अक्षमताओं को संबोधित करते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा, "नए कानूनी कोड फैसलों के लिए सख़्त समयसीमा, अनिवार्यक देरी को कम करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का आदेश देते हैं।"

उन्होंने कई प्रमुख विशेषताओं को भी रेखांकित किया :

- अब किसी भी पुलिस स्टेशन में ई-एफआईआर दर्ज की जा सकती है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो।
- एफआईआर की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ प्रदान की जाएंगी।
- आरोपी, पीड़ित और गवाह ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग ले सकते हैं।
- कार्यशाला में सीबीसी की उप निदेशक संगीता जोशी द्वारा एक सूचनात्मक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को विभिन्न मीडिया इकाइयों

और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रभावी संचार के महत्व और नए कानूनी ढांचे के बारे में जनता तक जानकारी पहुंचाने में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला।

अपने स्वागत भाषण में, पीआईबी के उप निदेशक हर्षित नारंग ने महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तनों को समझने और उनकी व्याख्या करने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। "पत्रकार सरकार और लोगों के बीच सेतु होते हैं। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों और उनके निहितार्थों को जनता को समझाने में आपकी भूमिका अमूल्य है।

इसी स्थान पर चंडीगढ़ के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। प्रदर्शनी में कई पैनेलों पर तीन नए आपराधिक कानूनों के विस्तृत प्रावधानों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी ने उपस्थित लोगों को नए कानूनों की एक दृश्य और व्यापक समझ प्रदान की। कार्यशाला का समापन एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जहाँ पत्रकारों को वक्ताओं के साथ जुड़ने और नए कानूनों के बारे में अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने का अवसर मिला।

भाजपा को सच में किसानों की चिंता है तो एमएसपी गारंटी कानून बनाए : आप

कृषि की लागत 70 प्रतिशत बढ़ गई और एमएसपी में वृद्धि सिर्फ 7 प्रतिशत की गई है, यह बहुत कम है : आप प्रवक्ता बब्बी बादल

• जालंधर बीज, चंडीगढ़

केन्द्र सरकार द्वारा इस साल खरीफ फसलों की एमएसपी में मामूली वृद्धि किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा किसान हितैषी होने का ड्रामा कर रही है। पार्टी ने कहा कि अगर भाजपा को सच में देश के किसानों की चिंता है तो वह किसानों की मांग के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून बनाए।

वैचार को पार्टी मुख्यालय चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप प्रवक्ता हरसुखिंदर सिंह बब्बी बादल ने कहा कि पिछले कई सालों में कृषि की लागत करीब 70 प्रतिशत बढ़ गई है और मोदी सरकार एमएसपी में मात्र 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर खुद से अपनी पीठ थपथपा रही है।

उन्होंने कहा कि खुद मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 83 प्रतिशत फसलें एमएसपी से कम कीमतों पर बिकती हैं। मात्र 13 प्रतिशत फसल की ही एमएसपी पर खरीद की जाती है। कई राज्यों में तो फसलों की एमएसपी पर खरीद ही नहीं हो पाती। इसलिए एमएसपी पर यह वृद्धि 'टू लिटिल और टू लेट' है।

उन्होंने कहा कि किसानों को अभी आर्थिक संकट से निकालने के लिए एमएसपी पर मामूली वृद्धि की जरूरत नहीं है। देश का किसान तभी खुशहाल हो सकता है जब उसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार "C2 + 50%" के हिसाब से फसलों की कीमत अदा दी जाएगी। इसके अलावा फसल विविधीकरण के लिए किसानों को अलग से आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए।

उन्होंने कहा कि फसलों की कीमत और कृषि



से संबंधित नीतियां किसान संगठनों के सुझाव द्वारा तैयार की जाए। जब सरकार इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी लाती है तो अंबानी-अडानी और अन्य उद्योगपतियों के साथ राय-मशविरा करती है, फिर कृषि पर कोई नीति बनाने से पहले किसानों के साथ चर्चा क्यों नहीं की जाती?

दरअसल भाजपा सरकार किसानों का विकास चाहती ही नहीं है। वह सिर्फ अपने कुछ करीबी पूंजीपतियों का विकास चाहती है। वह किसानों के मेहनत का फल अपने पूंजीपति मित्रों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही किसान विरोधी और पूंजीपति समर्थक रही है। यह उसकी हर नीतियों में स्पष्ट तौर पर झलकता है।

उन्होंने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव के समय भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक

किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसानों की आय दुगुनी होने की बजाय उनकी आत्महत्या दोगुनी हो गई और कृषि की लागत दोगुनी हो गई। पेट्रोल-डीजल और अन्य कृषि सामग्रियों की कीमत दोगुनी हो गई। भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए।

बब्बी बादल ने पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ पर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी और सुनील जाखड़ की जोड़ी गप्पी और पप्पी की जोड़ी है। मोदी सरकार तानाशाही कानून बनाती है और सुनील जाखड़ उसपर टप्पा(मुहर) लगाते हैं। जाखड़ का काम केंद्र सरकार के हर फैसले पर सिर्फ ताली बजाना है। भाजपा में जाने के बाद उन्होंने कभी भी पंजाब के किसानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई।

स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं किसान : बाजवा

स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं किसान: बाजवा

• जालंधर बीज, चंडीगढ़

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्र की भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 117 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के बाद धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को वैध बनाने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि सिर्फ धोखा है। यह बहुत कम और बहुत देर से लिया गया निर्णय है। भाजपा सरकार इस तरह की रणनीति के साथ प्रदर्शनकारी किसानों को शांत करने की कोशिश कर रही है, हालांकि, उनकी लंबे समय से लंबित मांग डॉ एमएस स्वामीनाथन के सी 2 + 50% के फार्मूले के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी को कानूनी बनाने का वादा भी किया था।

डीजल, खाद, कोंटनाशक और मजदूरों की बढ़ती कीमतों के साथ, खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है। हालांकि, भाजपा ने इन तथ्यों पर ध्यान

नहीं दिया है। बाजवा ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस तरह की मामूली वृद्धि का प्रचार करके भाजपा हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों का लाभ उठाना चाहती है।

बाजवा ने कहा कि समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के अपने वादे को पूरा करें। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर पानी की नालियों, नालियों और तटबंधों को मजबूत करने में जमा गंदगी को साफ करने में टाल-मटोल करने के लिए आलोचना करते हुए बाजवा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप सरकार ने 2023 की बाढ़ से कोई सबक नहीं सीखा है। "यह विशेष रूप से किसान थे जो 2023 की बाढ़ के दौरान पीड़ित हुए हैं। लाखों एकड़ धान और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में जानवरों की मौत हो गई। बाजवा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा बार-बार किए गए वादों और आश्वासन के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिला है।



जालंधर वेस्ट उप-चुनाव : डिप्टी कमिश्नर ने स्ट्रांग रूम और गिनती केंद्र का किया दौरा



• जालंधर बीज, जालंधर

डिप्टी कमिश्नर-कम-ज़िला चुनाव अधिकारी डा.हिमांशु अग्रवाल ने विधान सभा हलका 034- जालंधर वेस्ट (अ.ज.) के उप चुनाव के मद्देनजर स्थानीय लायलपुर खालसा कालेज फार वूमैन में प्रस्तावित गिनती केंद्र और पोस्ट पोल ई.वी.एम. स्ट्रांग रूम का दौरा किया।

डिप्टी कमिश्नर ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसबीर सिंह और ए.डी.सी.पी. सुखविन्दर सिंह सहित प्रस्तावित गिनती केंद्र और स्ट्रांग रूम में प्रबंधों का बारीकी से जायजा लेते हुए अधिकारियों

को सभी प्रबंध चुनाव आयोग के निर्देशों अनुसार सुनिश्चित करने को कहा।

डा. अग्रवाल ने विधान सभा हलके के लिए 10 जुलाई को मतदान उपरांत स्ट्रांग रूम में रखी जाने वाली वोटिंग मशीनों की 24 घंटे निगरानी के लिए सी.सी. टी.वी. कैमरे, निर्विघ्न बिजली सप्लाई, आग से सुरक्षा के उपाय, सुरक्षा आदि के विवरण लेते हुए उक्त सभी प्रबंध आगामी तौर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गिनती केंद्र और स्ट्रांग रूम की फूल भूषण सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षा पक्ष से प्रबंध पुख्ता होने चाहिए।

डीसी ने राजस्व अधिकारियों को दी सख्त हिदायतें कहा- लोगों की परेशानी बर्दाश्त नहीं

कहा- तहसीलों में अपने कामों के लिए आने वाले लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आने चाहिए

• जालंधर बीज, जालंधर

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तहसीलों में अपने कामों के लिए आने वाले लोगों को किसी प्रकार की मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की परेशानी किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ ज़िला प्रशासकीय कंप्लैक्स में राजस्व विभाग के कामकाज का जायज़ा लेने के लिए मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को कहा कि लोगों तक विभाग की सेवाएं निर्विघ्न, उचित और समयबद्ध ढंग से पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने राजस्व विभाग के साथ सम्बन्धित सेवाएं के लिए प्राप्त आवेदन को निपटारा पहले के आधार पर यकीनी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि कामों में अनावश्यक देरी



के साथ सख्ती के साथ पूरा किया जाएगा। डा. अग्रवाल ने उप मंडल मैजिस्ट्रेटों को राजस्व विभाग के कामों की निगरानी यकीनी बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू सम्बन्धित कामों की व्यक्तिगत तौर पर नज़रसानी के लिए एस.डी. एम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आते विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित मीटिंगों करने जिससे राजस्व विभाग के साथ सम्बन्धित कामों की पैडेंसी को शून्य किया जा सके।

भ्रष्टाचार विरुद्ध 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने पर जोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तहसीलों में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा कोई मामला सामना आता है तो सख्त कार्यवाही अमल में लाई

जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी भ्रष्ट कार्यवाही के लिए लोग सम्बन्धित सब डिविज़न के एस.डी. एम. दफ्तर या सीधे तौर पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में पहुँच कर सकते हैं। इस दौरान रेवेन्यू कोर्ट अदालतों में लंबित मामलों को समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कहा कि 2 साल या इससे अधिक समय से पुराने मामलों का विशेष ध्यान देते जल्द से जल्द निपटारा यकीनी बनाया जाए। साथ ही उनकी रिकरवरी की प्रक्रिया को और तेज़ करने के निर्देश भी दिए। डिप्टी कमिश्नर ने इस दौरान जमाबंदियों की स्थिति, पटवारियों और कानून्गो की जांच, रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर जानकारी की नियमित अपडेशन, सीमा रेखा सम्बन्धित पैडेंसी, डिजिटल इज़ड केडस्ट्रल मेप की प्रगति आदि का भी जायज़ा लिया। बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमित महाजन, एस.डी.एमज़, ज़िला राजस्व अधिकारी नवदीप सिंह भोगल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

ईपीएफओ में अप्रैल 2024 के दौरान सर्वाधिक 18.92 लाख सदस्य जुड़े

• जालंधर बीज, नई दिल्ली

20 जून, 2024 को जारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतिम पेरिड डेटा से पता चलता है कि ईपीएफओ ने अप्रैल 2024 के महीने में 18.92 लाख सदस्य जोड़े हैं। यह वृद्धि अप्रैल 2018 में पहले पेरिड डेटा प्रकाशित होने के बाद सर्वाधिक है। पिछले महीने मार्च 2024 की तुलना में चालू महीने के दौरान सदस्यों की संख्या में 31.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, वर्ष-दर-वर्ष विश्लेषण से पता चलता है कि अप्रैल 2023 की तुलना में सदस्यों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सदस्यता में इस वृद्धि को विभिन्न कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कर्मचारी लोगों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के आउटरीच कार्यक्रमों की प्रभावशीलता शामिल है। डेटा से पता चलता है कि अप्रैल 2024



के दौरान लगभग 8.87 लाख नए सदस्य नामांकित हुए हैं। डेटा का एक उल्लेखनीय पहलू 18-25 आयु वर्ग कर्मचारी है जो अप्रैल 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों का महत्वपूर्ण 55.50 प्रतिशत है। यह महीने की प्रवृत्ति के अनुरूप है जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं, मुख्य रूप से पहली बार नौकरी करने वाले हैं। पेरिड डेटा से पता चलता है कि लगभग 14.53 लाख सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बाहर निकल गए थे और बाद में इसमें शामिल हो गए। यह आंकड़ा मार्च 2024 के पिछले महीने की तुलना में 23.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदली और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए। अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपने संचय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना।

सरकार पठानकोट की लीची को विदेशों में भेजने की करेगी शुरुआत, चेतन सिंह जौड़ामाजरा का ऐलान

• जालंधर बीज, चंडीगढ़/पठानकोट

पंजाब सरकार द्वारा राज्य में सबसे बढ़िया गुणवत्ता वाली ज़िला पठानकोट की लीची को विदेशों में भेजने की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही भूमिगत जल पर किसानों की निर्भरता को भी घटाया जा सकेगा। यह ऐलान बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने आज सुजानपुर स्थित लीची ज़ोन में मनाए जा रहे राज्य स्तरीय लीची प्रदर्शनी और विचार गोष्ठी के दौरान किया। इस मौके पर उनके साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले और वन एवं वन्य जीव सुरक्षा मंत्री लाल कंद करारुचकक विशेष तौर पर उपस्थित रहे।

जौड़ामाजरा ने कहा कि पंजाब में सबसे बढ़िया क्वालिटी की लीची ज़िला पठानकोट में पाई जाती है और पूरे पंजाब में की जा रही



लीची की पैदावार में 60 प्रतिशत योगदान ज़िला पठानकोट का है। किसानों को लीची की पैदावार के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार प्रयास करेगी कि ज़िला पठानकोट की लीची विदेश तक पहुँचे और इस कार्य के लिए जल्द ही लीची की खेप विदेश के लिए रवाना की जायेगी।

नीट परीक्षा मामले में एनपीए की चुप्पी ठीक नहीं : आप

'आप' ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच के लिए एसआईटी की मांग की, कहा- जांच में केन्द्र सरकार की दखलंदाजी न हो

• जालंधर बीज, चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने 5 मई को नीट परीक्षा में शामिल हुए 24 लाख छात्रों के भविष्य को खतरों में डालने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की। पार्टी ने इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी बनाने की अपील की और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

गुरुवार को पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते



हुए 'आप' प्रवक्ता बिक्रमजीत पासो ने प्रश्नपत्र लीक, रिजल्ट की तिथि, ग्रेस मार्क्स और इस मामले पर एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की चुप्पी में सवाल उठाए। आप नेता ने कहा कि हम इस मामले पर किसी की चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। इस मामले को हलके में नहीं लिया जा सकता। (प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ

एडवोकेट इंद्रजीत सिंह और गगनदीप सिंह भी मौजूद थे।)

बिक्रमजीत पासो ने कहा कि नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी और इसका रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन एनटीए ने आम चुनाव के नतीजों की अफरा-तफरी के बीच 4 जून को ही रिजल्ट घोषित कर दिया। उसने 67 छात्रों को 720/720 अंकों के साथ टॉपर घोषित किया। फिर ऐसे छात्र भी रहे, जिन्हें 719, 718, 717 आदि अंक मिले, जो अस्मभव है। इस परीक्षा में सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 4 अंक दिए जाते हैं, निगेटिव मार्किंग भी होती है, गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाता है। इसलिए 715, 710, 705 और इसी तरह के अंक हो सकते हैं, लेकिन 719, 718, 717 आदि नहीं।

उन्होंने गलत अंक देने को ग्रेस अंक बताकर सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी ग्रेस अंक देने के आधार और नियमों को सांख्यिक रूप से नहीं बताया। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र यह परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 16 से 18 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। इसलिए एनटीए पारदर्शी और पहले से उल्लेखित प्रक्रिया के बिना अपनी पसंद के कुछ चुनिंदा छात्रों को ग्रेस अंक नहीं दे सकता।

पासो ने कहा कि कुछ छात्रों ने प्रश्नपत्र लीक किए थे। छात्रों ने स्वीकार किया है कि परीक्षा से पहले उनके पास बिल्कुल वही प्रश्नावली थी, लेकिन एनटीए ने इसे ठीक से संबोधित करने के बजाय सिर्फ एक प्रेस विज्ञापित जारी की कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ।

पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 1.71 करोड़ रुपए की राशि जारी

• जालंधर बीज, चंडीगढ़

पंजाब सरकार प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए लगातार यत्नशील है, वहीं पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए आशीर्वाद योजना के अंतर्गत मालेरकोटला जिले के लिए 1.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मालेरकोटला जिले के पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के 337 लाभप्राप्तियों के लिए 1.71



करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस राशि में दिसंबर 2022 से मार्च 2023 के 337 लाभप्राप्तियों को कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 के 84, जनवरी 2023 के 68, फरवरी 2023 के 80 और मार्च 2023 के 105 लाभप्राप्तियों को कवर किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाकी लंबित पड़े मामलों को भी जल्द ही कलियर किया जाएगा।

बीसीसीआई ने जारी किया घरेलू सीजन का शेड्यूल

स्पॉट्स डेस्क. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भी भारतीय टीम का व्यस्त शेड्यूल रहने वाला है। इस दौरान भारत बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम की मेजबानी करेगा। दरअसल, बीसीसीआई ने भारतीय टीम सत्र 2024-25 का घरेलू शेड्यूल जारी किया है। इसका आगाज 19 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से होगा। बता दें कि भारतीय टीम सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट और तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 19 से 23 सितंबर 2024 और दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 को खेला जाएगा। जबकि टी20 मुकाबले 6, 9 और 12 अक्टूबर को खेले जाएंगे। वहीं, बांग्लादेश के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगी। जहां दोनों टीमें के बीच तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे। जो कि, 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 1 नवंबर से शुरू होंगे। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम



फोटो- बीसीसीआई

इस बार फिर भारत का लंबा दौरा करेगी। यहां 22 जनवरी 2025 से 12 फरवरी तक दोनों के बीच 5 टी20 और 3 वनडे सीरीज खेले जाएंगे। इंग्लैंड टीम यहां पहले 22 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 5 टी20 मैच खेलेगी। इसके बाद दोनों के बीच 6 फरवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 के बीच वनडे मैच खेले जाएंगे।

गुरमीत सिंह खुडियां ने 8 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र



• जालंधर बीज, चंडीगढ़

पंजाब के कृषि और किसान भलाई, पशु पालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्रों स.गुरमीत सिंह खुडियां ने आज यहाँ अपने दफ्तर में कृषि और मछली पालन विभाग में नए भर्ती हुए आठ युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।

कृषि और किसान भलाई विभाग में तीन लैब टेक्नीशियन और दो क्लर्कों को नियुक्ति पत्र बाँटे गए। इन दोनों क्लर्कों को अनुकंपा के आधार पर भर्ती किया गया है। इसके इलावा मछली पालन विभाग में एक जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर और दो स्टैनो टाईपिस्टों को भी नियुक्ति पत्र

दिए गए हैं। गुरमीत सिंह खुडियां ने नव-नियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते पूरी इमानदारी और समर्पण की भावना से ड्यूटी निभाने के लिए कहा क्योंकि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की लोगों को सेवाएं प्रदान करने सम्बन्धित नीति में इमानदारी, कार्यकुशलता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है जिससे आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि पंजाब में मुख्य मंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अब तक 42, 000 से अधिक युवाओं को मैरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों दी गई है।